

प्रेषक,

डॉ०उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग—1

देहरादून:दिनांक 29 जून, 2012

विषय:—नगर निगम, देहरादून के अकेन्द्रीयित सेवा के दिनांक 01-01-2006 को अथवा
इसके पश्चात् सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी एवं
राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1190 / IV(1) / 2009—01(72) / 2008 दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के नगर निगम में कार्मिकों के वेतनमान का दिनांक 01—01—2006 से पुनरीक्षण किया गया है। वेतन समिति उत्तराखण्ड 2008 के प्रथम प्रतिवेदन में पेंशनर्स/ पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन, ग्रेच्युटी तथा पेंशन राशिकरण के संबंध में की गयी संस्तुतियों को संकल्प संख्या—394 / xxxiv(07)2008 के अधीन दिनांक 01—01—2006 को अथवा इसके पश्चात् सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन/ पारिवारिक पेंशन/ ग्रेच्युटी तथा पेंशन राशिकरण के नियमों एवं दरों को नगर निगम देहरादून के सेवानिवृत्त पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन लागू किये जाने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1—यह आदेश नगर निगम देहरादून के सभी सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू होगें किन्तु यह आदेश दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से लागू की गयी नयी अंशदान पेंशन योजना के सेवकों पर लागू नहीं होगी।

2—(क) इस आदेश की अधीन की जा रही व्यवस्थाएं उन कर्मचारियों पर लागू होगीं जो 01—01—2006 को अथवा सेवा में रहते हुए दिवंगत हुए हैं।

• (ख) जिन सेवकों के मामले में दिनांक 01—01—2006 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/ पारिवारिक पेंशन/ मृत्यु एवं सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी का निर्धारण भुगतान किया जा चुका हो, का पुनरीक्षण इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनरों के लिए लाभप्रद न हो, तो उन प्रकरणों में ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

3—(1) परिलक्षियां—पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तक लाभों (सेवानिवृत्तिक—ग्रेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलक्षियों से तात्पर्य उस वेतन से है, जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—02, भाग—2—4 के मूल नियम 9(21)(1) में

परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि के ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

(2) वेतन— का आशय वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के अनुक्रम में राजकीय कर्मचारियों के दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान विषयक शासनादेश संख्या 395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर-5 के अनुसार निर्धारित वेतन बैंड में अनुमन्य वेतन तथा लागू ग्रेड-वेतन का योग होगा, जिसमें विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन एवं अनुमन्य अन्य प्रकार का वेतन सम्मिलित नहीं होगा।

(3) सेवानैवृत्तिक/डेथ कम ग्रैच्यूटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को अनुमन्य महगाई भत्ते को सम्मिलित किया जाएगा।

4—पेंशन— पेंशन की गणना पूर्व की भांति औसत परिलक्षियों के 50 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी, परन्तु न्यूनतम पेंशन की धनराशि रु0 3500 प्रतिमाह तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन (1-1-2006 से रु0 80,000/-) के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। राज्य सरकार की पेंशन की दरों के संबंध में पूर्व में की गई व्यवस्था उक्तानुसार संशोधित समझी जाएगी। यदि कोई सेवक एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो समस्त पेंशन की धनराशि जोड़कर न्यूनतम रु0 3500/- से कम न हो, का आगणन किया जाय तब न्यूनतम पेंशन रु0 3500/- निर्धारित की जायेगी।

5—पेंशन की अनुमन्यता हेतु अर्हकारी सेवा—

(1) 10 वर्ष से कम की अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी तथा ऐसी स्थिति में पूर्व की भांति केवल सर्विस ग्रैच्यूटी अनुमन्य होगी।

(2) पूर्ण पेंशन हेतु 33 वर्ष की सेवा की अर्हता को घटाकर अब 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगी।

(3) 20 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर अंतिम माह में आहरित वेतन या 10 माह की औसत परिलक्षियां जो भी कर्मचारी को लाभकारी हो, के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य होगी। जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है, उनके लिए भी उक्त व्यवस्था समान रूप से लागू होगी।

(4) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति हेतु अवशेष सेवा अथवा अधिकतम पांच वर्ष जो भी कम हो की सेवा जोड़ने की व्यवस्था अब समाप्त की जा रही है। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 के भाग 2-4 के मूल नियम-56 में आवश्यक संशोधन यथासमय कर दिया जायेगा।

(5) 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने पर ही अर्ह सेवा 20 वर्ष के औसत में पेंशन का आगणन किया जाय।

6—सेवानैवृत्तिक ग्रैच्यूटी/मृत्यु ग्रैच्यूटी— सेवानैवृत्तिक ग्रैच्यूटी/मृत्यु ग्रैच्यूटी की अधिकतम धनराशि की सीमा रु 10.00लाख(रु0 दस लाख मात्र) से अधिक नहीं होगी। इस विषय में अधिकतम अवधि 33 वर्ष में प्रति वर्ष 15 दिन का मानक पूर्ववत रहेगा।

7. पारिवारिक पेंशन—

(1) पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर सामान्य रूप से की जायेगी। पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रु0

3500 प्रतिमाह होगी तथा अधिकतम धनराशि वेतन के 30 प्रतिशत तक सीमित होगी। इस सन्दर्भ में पारिवारिक पेंशन की दरों से संबंधित व्यवस्था दिनांक 1-1-2006 से तदनुसार संशोधित समझी जायेगी। दिवंगत हुये सेवक के प्रकरण में अन्य प्रक्रियाओं को यथावत रखते हुए बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन, अब 7 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष पर अनुमन्य होगी।

(2) पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु 'परिवार' की परिभाषा पूर्ववत निम्नलिखित होगी—

(क) दिनांक 1-1-2006 के पूर्व की व्यवस्था के अधीन परिवार की परिभाषा निम्न प्रकार निर्धारित है—

(1) पत्नी/पति

(2) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम के पुत्र को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे तो जीविकोपार्जन की तिथि अथवा 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

(3) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम की अविवाहित पुत्री को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे या उसका विवाह हो जाए अथवा 25 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। उपरोक्त सन्तानों में सौतेली तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व विधिवत गोद ली गयी सन्ताने भी समिलित है। विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त सन्तानों पर आयु का बन्धन नहीं है तथा संबंधित आदेश के प्रतिबन्धों के अधीन पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र होंगे। दिनांक 1-1-2006 से विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को भी परिवार में समिलित माना जाएगा। दिनांक 1-1-2006 से यह भी व्यवस्था की जाती है कि यदि स्वर्गीय सरकारी सेवक के परिवार में उसकी पत्नी तथा उपर्युक्त वर्णित श्रेणी की पात्र सन्तान नहीं है, तो उसके माता/पिता जो उस पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, को उसके परिवार में समिलित समझा जाएगा। पूर्णतया आश्रित होने पर जीविकोपार्जन से संबंधित मासिक आय के संबंध में स्पष्टीकरण अलग से जारी किया जाएगा और तब तक पूर्ण मासिक आय की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

8. पेंशन के एक भाग का राशिकरण—पेंशन के एक निर्धारित भाग अर्थात् 40 प्रतिशत तक की धनराशि की संशोधित दरों पर अनुमन्य होगा। राशिकरण की व्यवस्था दिनांक 1-1-2006 से लागू न होकर तत्काल प्रभाव से कार्यालय ज्ञाप निर्गत किये जाने की तिथि से ही लागू होगी। कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से जो राशिकरण कर दिया गया उसका पुनरीक्षण/वसूली नहीं की जायेगी, परन्तु यदि वर्तमान में कोई 40प्रतिशत की सीमा में पुनः राशिकरण करना चाहता है तो वर्तमान दरों पर ही राशिकरण किया जाय।

9. इन आदेशों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महंगाई राहत की गणना राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशानुसार की जाय।

10. 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को 1-1-2006 से अनुमन्य पेंशन पर निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य कराया जाय:-

पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनरों की आयु	पेंशन में वृद्धि
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत
95 वर्ष से 100 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत

उपरोक्तानुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने हेतु पेंशन वितरण प्राधिकारी द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्र में अनिवार्य रूप से पेंशन/पारिवारिक पेंशनर्स की अतिरिक्त पेंशन का अलग से उल्लेख किया जायेगा तथा पारिवारिक पेंशनर द्वारा अपनी आयु की पुष्टि हेतु अभिलेख आदि पेंशन स्वीकर्ताधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी पेंशन प्राधिकार पत्र में मूल पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की आयु की प्रविष्टि तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ करेंगे।

11—दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर आगणित पेंशन एवं ग्रेचुटी की 31-8-2008 तक की देयता का 40 प्रतिशत 2008-09 तथा 60 प्रतिशत 2009-10 को नगद भुगतान किया जायेगा।

12—दिनांक 01-01-2006 के बाद सेवा त्यागने/कर्मचारियों की मृत्यु होने के प्रकरणों में नगद भुगतान किया जायेगा।

2—उक्त के फलस्वरूप होने वाले व्यय-भार का वहन नगर निगम द्वारा अपने वित्तीय स्रोतों से किया जायेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक से कोई सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

3—उक्त के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये संशोधन आदेश/कार्यालय झाप के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

4—यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक यथोपरि।

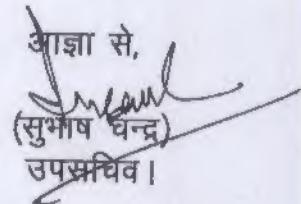
भवदीय,

→
(डॉउमाकान्त पवार)
सचिव।

29, पृष्ठ
संख्या- 266 / IV(1) / 03 (न०वि) / 2001, दिनांक अप्रैल, 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2-आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3-जिलाधिकारी, देहरादून।
- 4-निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवायें सह स्टेट इन्टरनल अडिटर उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 5-मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
- 6-वित्त (वै०आ०-सा०नि०) अनुभाग-७।
- 7-निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 8-गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उपसचिव।